GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR) MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA) (RAILWAY BOARD)

No. F(E)III/2000/PN1/57.

NEW DELHI

Dated: 15.06.2004

The General Managers & FA&CAOs, All Zonal Railways & Production Units.

Sub: Payment of gratuity to Government/Railway servants retired during the period from 1.7.93 to

31.3.95 ----reg.

Ref: Letter No. F(E)III/2000/PN1/57 dt. 24.3.2004.

A large number of original applications are being filed before the Hon'ble Tribunals by the Railway servants retired during 1.7.1993 – 31.3.95 seeking directions for payment of DCRG on the basis of the judgement passed by CAT/Mumbai Bench on 21.9.2001 in OA Nos. 542,942 & 943 of 97 filed by Shri B.S. Dhuri & Others. The latest position in respect of this judgement has already been conveyed vide Board's letter of even number dt. 24.3.2004 to facilitate Railway administration to draft suitable counter replies. In continuation, a note containing the factual position about the decision of the Government in regard to reckoning of emoluments for determining DCRG, and a copy of recent order of CAT/Bangalore Bench on a cluster of OAs of similar nature, are enclosed as Annexure I & II.

- 2. Moreover, in the OAs No. 408 & 489 491/2003 filed by Sri S. Manickam & others, the Hon'ble CAT/Banglore allowed the applications vide orders dt. 04.11.2003 on the basis of CAT/Mumbai Bench's judgement in the case of Sh. B.S. Dhuri & others referred to in para 1 above. The Railway Administration filed Writ Petition No. 17929-32/2004 before the Hon'ble High Court, Banglore against the order dt. 04.11.2003. The Hon'ble High Court heard the petition on 24.05.2004 and stayed the operation of order dt. 04.11.2003 passed by the Hon'ble CAT/Banglore.
- 3. Of late, OAs are also being filed by the Railway servants retired during 1.1.1986 31.12.1995 for grant of DCRG on the basis of judgement dt.13.2.2002 of the Hon'ble Supreme Court in Civil Appeal No. 937 of 1995 UOI Vs. Pritam Singh. A note explaining the circumstances under which this judgement has gone against the Railways is enclosed as Annexure III.

- 4. The contents of the note enclosed as annexures may be suitably incorporated in the replies to the OAs, writ petitions etc. which are required to be filed by the Railways.
- 5. Please acknowledge receipt.

(S.SREERAM)

Dy. Director Finance (Estt.)III.,

Railway Board.

Payment of gratuity to (III of I enuxennA slond servents retired during the period from 1.7.93 to

Copy to: EDPC-I, DPC, EDV(E), DS(D), EDE(Res), EDE, JS, JS(G), JS(E), E(G), ERB-I, II, III, E(O)I,II,III and (CC), PC-III, IV, V, E(P&A)I, II.

A large number of original applications are being filed before the Honble Tribunals by the Railway servants retired during 1.7.1993 – 31.3.95 seeking directions for payment of DCRC, on the basis of the judgement passed by CAT/Mumbai Bench on 21.9.2001 in OhMos. 542.942.8.943.01.97 passed by Shri B.S. Dhuri & Others. The latest position in respect of this independnt has already been conveyed vide Board's letter of even number dt. 24.3.2004 to facilitate Railway administration to draft suitable counter replies. In continuation, a note containing the factual position about the decision of the footbrustion, a note containing the factual position about the decision of the facilitate Railway administration about the decision of the facilitate regard to reckoning of emoluments for determining DCRC, so and a copy of recent order of CAT/Bangulore Bench on a diviser of OAs of similar nature, are enclosed as Annexure I & II.

Moreover, in the OAs No. 408 & 489 - 491/2003 filed by Sri S. Manickam & others, the Hon'ble CAT/Banglore allowed the applications vide orders of the the basis of CAT/Mumbar Bench's judgement in the orders of the O4.11.2003 on the basis of CAT/Mumbar Bench's judgement in the orders of Sh. B.S. Dhuri & others referred to in peral above. The Railway case of Sh. B.S. Dhuri & others referred to in peral the Hon'ble High Court Administration filed Writ Petition No. 17929-32/2004 before the Hon'ble High Court Court, Banglore against the order of the operation of order dischard the petition on 24.05.2004 and stayed the operation of order dischard the petition on 24.05.2004 and stayed the operation of 24.05.2004 and stayed the operation of the Hon'ble CAT/Banglore.

04.11.2003 passed by the Hon'bie CAT/bianglore

3. Of late, OAs are also being filed by the Railway servants retired during continue to the basis of judgement of DCRC on the basis of judgement of DCRC on the basis of judgement of 1.11886 - 31.12.1995 for grant of DCRC on the Covil Appeal No. 907 of 1995 of the Hon'bie Supreme Court in Civil Appeal No. 907 of this this which this carcumstances under which this

भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

्र (क) III/2000/पी एन 1/57

नई दिल्ली, दिनांक: 15.06.2004

व वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, व वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, व वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी,

विवय: 1.7.93 से 31.3.95 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए सरकारी/रेलवे सेवकों को उपदान का भुगतान करने के संबंध में.

संदर्भ : 24.3.2004 का पत्र सं. एफ (ई)III/2000/पी एन 1/57.

1.7.1993-31.3.95 के दौरान सेवानिवृत्त हुए रेलवे कर्मचारियों द्वारा माननीय अधिकरणों के समक्ष भारी संख्या में मूल आवेदन दायर किए जा रहे हैं, जिनमें श्री बी.एस. धुरी एवं अयों द्वारा दायर किए गए 97 के मूल आवेदन सं. 542, 942 एवं 943 के संबंध में केन्द्रीय प्रशासिनक अधिकरण/मुंबई पीठ द्वारा 21.9.2001 को पारित निर्णय के आधार पर मृत्यु एवं प्रशासिनक अधिकरण/मुंबई पीठ द्वारा 21.9.2001 को मांग की गई है. इस निर्णय के संबंध में निर्देश देने की मांग की गई है. इस निर्णय के संबंध में विनतम स्थिति बोर्ड के 24.3.04 के समसंख्यक पत्र के तहत पहले ही संसूचित कर दी गई है कि प्रशासन को उपयुक्त प्रत्युक्तर तैयार करने में सुविधा हो. इसी क्रम में, मृत्यु एवं संवानिवृत्ति उपदान का निर्धारण करने के लिए परिलिध्धियों की गणना करने के संबंध में सरकार के विणय के बारे में तथ्यात्मक स्थिति से संबंधित नोट तथा इसी प्रकार के कई मूल आवेदनों पर किंद्रीय प्रशासिनक अधिकरण/बैंगलूरू पीठ के हाल हो के आदेशों की प्रति अनुबंध I और II पर संलान है.

2. इसके अलावा, श्री एस. माणिक्कम तथा अन्यों द्वारा दायर किए गए 2003 के मूल आवेदन सं. 408 एवं 489-491 के संबंध में माननीय केन्द्रीय प्रशासिनक अधिकरण/बैंगलूरू ने उपयुंक्त पैरा 1 में उल्लिखित श्री बी.एस. धुरी एवं अन्यों के मामलों में केन्द्रीय प्रशासिनक अधिकरण/मुंबई पीठ के निर्णय के आधार पर 4.11.2003 के आदेशों के तहत आवेदनों को अनुमित दे दी है. रेलवे प्रशासन ने 4.11.2003 के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका सं. 17929-32/2004 दायर की है. माननीय उच्च न्यायालय ने 24.05.2004 को याचिका की सुनवाई की तथा माननीय केन्द्रीय प्रशासिनक अधिकरण/बैंगलूरू इस पारित किए गए 4.11.2003 के आदेशों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी.

3. हाल ही में, भारत संघ बनाम प्रीतम सिंह 1995 की सिविल अपील सं. 937 में माननित्र उच्चतम न्यायालय के 13.2.2002 के निर्णय के आधार पर मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान प्रदान किए जाने के लिए 1.1.1986-31.12.1995 के दौरान सेवानिवृत्त हुए रेल कर्मचारियों हारा मूल आवेदन दायर किए जा रहे है. एक नोट अनुबंध III के रूप में संलग्न है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि किन परिस्थितियों में यह निर्णय रेलवे के विपक्ष में गया है.

4. अनुबंधों के रूप में संलग्न नोट की विषयवस्तु को मूल आवेदनों के उत्तरों, सिट याचिकाओं इत्यादि जिन्हें रेलों द्वारा दायर किया जाना अपेक्षित है, में उपयुक्त रूप से शामिल किया जाए.

कृपया पावती दें.

जी उपदान का भूगतान करने के संबंध में.

मीकरणों के समक्ष भारी संख्या में मूल आवेदन दायर किए जा रहे हैं, जिन्हों. M र्म I ब्रह्मां : नग्लंम

अयां द्वारा दायर किए गए 97 के मूल आवंदन सं. 542, 942 एवं 943 के संबंध से केन्द्रोय प्रशासनिक अधिकरण/मूंबई पीठ द्वारा 21.9.2001 को पारित निर्णय के आधार एर मृत्यू एवं संबानिवृत्ति उपदान के भूगतान के संबंध में निर्देश देने की यांग की गई है. इस निर्णय के संबंध में निर्वान पर्यात स्थिति वार्ड है. इस निर्णय के संबंध में निर्वान पर्यात की उपयुक्त प्रत्यूतर तैयार करने में सुविश्व हो संबुचित कर दी गई है जाकि रेल प्रशासन को उपयुक्त प्रत्यूतर तैयार करने में सुविश्व हो इसी क्रम में, मृत्यू एवं मंत्रातिवृत्ति उपदान का निर्यारण करने के लिए परिकृत्यियों की गणना करने के संबंध में नरकार के निर्णय के बारे में तथ्यात्मक स्थिति से संबंधित नोट तथा इसी प्रकार के कई मूल आवंदनों पर केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण/बेंगलुक पीठ के हाल हो के आदेशों की प्रति अनुबंध 1 और 11 पर

इसके अल्लावा, औ एस. व्याणिककम तथा अन्यों द्वारा किए गए 2003 के मूल शायेदन मं. 408 एवं 489-491 के संबंध में पाननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण/वंगल्क ने अप्यंत्रा पेरा 1 में उल्लिखित श्री की एस. यूरी एवं अन्यों के पापलों में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण/मुंबई पीठ के निर्णय के आधार पर 4.11.2003 के आदेशों के तहत आयेदनों को अधिकरण/मुंबई पीठ के निर्णय के आधार में 4.11.2003 के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के अनुमति वं दो है. रेलवे प्रशासन ने 4.11.2003 के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समुमति वं दो है. रेलवे प्रशासन में 4.11.2003 के अपदेशों के कार्याच्या पर रोक लगा दी.

Annexure-I

The percentage of DA constituting DP for reckoning gratuity in the IVth Pay commission scales of pay

The 4th Central Pay Commission recommendations came effect from 01.01.1986. As per the decision of the government into enest recommendations, gratuity was payable to the retiring on the sale based on the last basic pay drawn in the time scale employees at the time of retirement from service. applicable has been clamour from the Staff side members of the Joint consultative Machinery (JCM) for a long time for treating part of Consultations Allowance (D.A.) as Dearness Pay (D.P.) for the the purpose of fixing gratuity. In the course of discussion in JCM, the Union Government conceded for merger of a portion of the DA as Op for the purpose of computation of gratuity, in the year 1992-Accordingly, the Union Government issued a 1993. communication in the year 1993 directing treatment of DA component as it stood on 1.7.1988 as DP for the purpose of computation of gratuity (which stood at 20% of the basic pay). In compliance with Union Government's decision, the Railway Board issued letter No. PC/IV/93/DP/1, dated 25.11.1993 directing extension of similar benefits to all the Railway employees, who retired on or after 16.09.1993.

On the demand of Staff side members of JCM, the Union Government constituted 5th Central Pay Commission by resolution dated 09.04.1994 to make recommendations as to pay structure, including retiral benefits, having regard to the economic conditions in the country and the resources of the Central Government. The Pay Commission was headed by the Hon'ble Mr. Justice Ratnavel Pandian, a former Judge of the Supreme Court. One of the terms of the reference to the Pay Commission was to consider the demand of "staff side members of JCM" to treat the D.A. component as DP including the 20% that has been already granted and submit interim report thereon, if the submission of the final report was not feasible within a period of 18 months from the date of its appointment. The 5th Pay Commission submitted its second interim report on 02.05.1995 recommending that DA linked to all India Consumer Price Index of 1201.66 may be treated as

DP to form part of emoluments for calculating gratuity and the DP to form part of emblurients of the ceiling limit of gratuity be enhanced to Rs. 2.50 Lakhs. The 5th Pay Commission recommended specifically that its Interim Report should be implemented only prospectively i.e. w.e.f. 1.4.1995. The Union Government accepted these recommendations communicated its decision. The Railway Board accordingly issued a circular dated 08.08.1995 directing implementation of the above said decision of the Union Government. Therefore, the said decision would apply to the employees who retired from service/ died on or after 01.04.1995. Having regard to the above decision. 97% of D.A. was liable to be included as D.P. for the purpose of computation of gratuity in the case of employees drawing basic pay up to Rs. 3500/-, 73% of D.A. as D.P. subject to minimum of Rs.3,395/- in the case of employees drawing basic pay above Rs.3,500/- and up to Rs. 6,000/- and 63% of D.A. as D.P. subject to minimum of Rs. 4,380/- in the case of employees drawing basic above Rs.6000/-.

- (iii) In view of the aforesaid position obtaining by virture of implementation of the recommendations of 5th Pay Commission, the applicants who had retired during 1.7.1993 to 31.3.1995 are not entitled to plead for equating them with employees, retired on or after 1.4.1995 and that the OA filed by such of the applicants obviously on second thought or belated thought is not maintainable in law.
- 2. The Hon'ble CAT/Bangalore Bench, while disposing of a cluster of OAs of similar nature, have observed that (i) the present application can be disposed of as the Hon'ble Supreme Court in their order dt. 6th January 2003 passed in SLP (Civil) No. 18367/02 have not only granted the Leave against the order and judgement of Punjab and Haryana High Court but even stayed the operation of the said judgement; (ii) based on the said order dt 6th January 2003, Chandigarh Bench of the Tribunal in RA No. 134/02 in OA 636/PB/2002 passed order dated 6th June 2003 and recalled and modified its earlier order dt. 10 th July 2002. and (iii) it was further ordered therein that the applicant would be granted the benefit as prayed for only after the outcome of the decision of the Supreme Court. Accordingly the Bangalore Bench of the Tribunal disposed

of the application with the direction that the claim of the applicants of the applicants of DCRG would be based on the judgment to be for a level by the Hon'ble Supreme Court in civil and the applicants of revisions the Hon'ble Supreme Court in civil appeal and rendered petitions/appeals as cited above A converse and rendered petitions/appeals as cited above. A copy of CAT's order connected petitions/appeals as Annexure-II connect 2.4.2004 is enclosed as Annexure-II.

- Stay has been granted by the High Court of Andhra Pradesh 3. 12.12.2003 in WMP No. 32918/2003 filed by the Railways of order passed on 29.7.2003 in PA No. 44.50 against order passed on 29.7.2003 in RA No. 11/2003 in OA No. against 2002. In WP MP No. 33175 of 2002 in the Railways against 2002. In WP MP No. 33175 of 2003 in WP No. 26242 of 337 of and by LIOI and 2 others the 113 in WP No. 26242 of 337 of Led by UOI and 2 others, the Hon'ble High Court of Judicature of Andhra Pradesh, has ordered interim suspension of orders of CAT, Hyderabad Bench dated 3.9.2003 in OA No. order passed by CAT, Bangalore Berich on 30.10.2003 allowing identical OAs, on filing Writ Petition by the Department of Posts in the Hon'ble High Court of Karnataka challenging the CAT order, the same has been admitted. The Hon'ble High Court has also stayed the operation of impugned order dated 30.10.2003. case with regard to gratuity
 - The Government of India is within its competence to fix a cutoff date as per the guidelines prescribed by the Apex Court famously known as Nakara Case (1983 [1] SCC 305). Moreover, in the following cases, the Hon'b.e Supreme Court of India upheld the decision of the Government in fixing a cut-off date for grant of retirement benefits. date of retirement for the purpose of computat
 - 91(2) SCC 104-Indian Ex-Service League Vs. UOI

(b) 94(4)SCC 68 -UOI Vs. P.N.Menon

(c) 95 suppl SCC (4)592 -S.P.Ganguly Vs.UOI

(d) 2000 (1) SCC 205- State of Punjab & Anr. Vs.J.L. (e) 2002 SCC 1(L&S)234-State of WB & Anr.Vs WB Govt.

Pensioners' Association & others.

It is the prerogative of the Government to decide whether the new principles for computing gratuity should be given retrospective effect or not. The Hon'ble Supreme Court in State Government

Pensioners' Association and Another Vs. State of Andhra Pradesh Pensioners' Association and Another values of their retirement AIR 1986 SC 1907 has need that gratery of their retirement and prevailing basis as is obtained at the time of their retirement on the prevailing basis as is obtained at the date of retirement on the basis the amount got crystallized on the date of retirement on the basis the amount got crystallized on the date of retirement. Once gratuity is paid of the salary drawn on the date of retirement and closed. The paid of the salary drawn on the date of retirement and closed. There is on that footing, the transaction is completed and closed. There is on that footing, the transaction is compared in the context of no scope for upward or downward formula evolved in future upward or downward revision of the formula evolved in future unless the provisions on this behalf expressly unless the provisions of the Hon'ble Supreme Count retrospectively. In the said case the Hon'ble Supreme Count retrospectively. In the said case six scales by the very nature of observed that "... Improvements in pay scales by the very nature of observed that ... improvements in pay as to apply to only those who things can be made prospectively so as to apply to only those who things can be made prospectively so appeared revision. Those who are in the employment on the date of upward revision. Those who were in employment say in 1950, 1960 or 1970, lived spent and were in employment say in the saved, on the basis of the then prevailing cost of living structure saved, on the basis of the thoront invoke Article 14 in order to claim and pay scale structure, cannot invoke Article 14 in order to claim the higher pay scale brought into force say, in 1980. If upward pay revision cannot be made prospectively on account of Article case with regard to gratuity.....".

The Hon'ble Supreme Court in Ex-Service League Vs. Union of India AIR 1991 SC 1182, had observed that D.S. Nakara's judgement is one of limited application and there is no scope for enlarging the ambit of that decision to cover all claims made by the pension retirees. In the said D.S. Nakara's case, the Hon'ble Supreme Court struck down the classification of pensioners on the basis of their date of retirement for the purpose of computation of monthly pension since the same would have led to an anomalous situation in which employees in the same pay bracket would draw pension at different rates. In contra distinction, gratuity is a gratuitous payment given to an employee on discharge. Gratuity is an amount paid superannuation or death. unconnected with any consideration and not resting upon it. and has to be considered as something given freely, voluntarily or without recompense. Hence, retirement gratuity being one time payment and the quantum of the said payment would not have a bearing on the other retirement benefits of the

employee to be made in future so as to allege discrimination vis-à-vis a person who retired subsequently. Further, payment of gratuity is dependent on various economic factors that exist during the relevant time. It is for the employer to decide on the question of revising the quantum of gratuity from time to time and when such a decision is taken, the same can be made applicable only with reference to a cut off date. If a contrary stand is taken, the same would render the scheme unworkable.

ANNEXURE -II

Second Floor. B. D. A. Complex. Indiranagar, BANGALORE - 38

ORIGINAL APPLICATION NOS.

DATED:

APR 2004 72 to 776.908.909.913 to 937.940.943.944 29 7/2 40 943 944 967 968 988 40 943 944 967 968 988 40 990 994 996 998 999 1000 1003 177 1020 1024 1066 1067 1071 04 2003 01 03 37 42 ±0 44 89 ±0 99 (15) 116 ±0 121 138 ±0 1 166)±0 148 169 171 ±0 173 175 196 ±0 202 208 01.03 to 06. 138 to 141.146 281 to 243.259.260.264.267.269 2004.

AFFLICANT (S) : M. DANODARAN & ORS

RESPONDENTS

: UNION OF INDIA & ORS

- Shel A.R. Holla, Advocate, Shu A. IInd Floor, Ist Cross, No. 30 Complex, Gandhinagar, Sujatha Complex, Gandhinagar, BANGALORE - 560 009.
- 3. Shri M. Vasudeva Rao, Sr. CGSC, SRAC COURT BUILDINGS.
 HIGH COURT - 560 001.
- Shei Violinu Bhat, ACGSC. No. 24, Ist Hain, seshadripuram, BANGALORE - 560 020.
- 07. Shri V. Donalswamy, Advocate, Amaravathi Layout, BANGARAPET - 563 114.
- 09. Shel Jagadeeshgoud Fatil, Advocate, No. 191, IInd Main, Jyothinagar, Nagarbhavi Ist stage, BANGALORE -72.
- 11. Shri S. Sugumaran, ACGSC. No. 27, Ist Main, 2nd Floor, Chandrashekar Complex, Gandhinagar, BANGALORE -09.
- 13. Smt. Shantha Chellappa, Railway Counsel, No. 27/1, 3rd Cross, Sathyanarayana Temple Street, Ulsoon, BANGALORE - 560 008.

- 02. Shri. N. Amaresh, ACGSC, No. 24. Ist Main, Seshadripuram, BANGALORE - 560 020.
 - 04. Shri Raghavendra Gayathri, Advocate, No. 22, Ist Floor Nehrunagar, SANGALORE-20.
 - 06. Shai V.N.Holla, ACGSC. No.17, 7th 'C' Main. Bandeppa Garden. Muthyala Nagar, BANGALORE - 560 054
 - 08. Shri ANV.Gowda,RLy Counsel No.8/2,Upstairs,R.V.Road. BANGALORE - 560 004.
 - 10. Smt. Shwetha Anand, Railway Counsel, No.145, 0-2,5th Cross, Krishna Residency, Gandhinagar, BANGALORE - 560 009.
 - 12. Shri K.N.Chandrashekar. ACGSC, No.180, 9th Main, 2nd Cross, BCC Layout, BANGALORE - 560 040.
 - 14. Shri M.S. Anandaramu. Advocate, No. 11, Ist Floor Ist Cross, S.C.Road Cross.
 Opp: Movelland Theatre, R.K. Puram, BANGALORE - 09.
- 15. Shil B. Venkateshan, Advocate, No. H-44, 4th Cross. Magadi Road, BANGALORE - 560021.

JBJECT: Forwarding of copies of the Orders passed by the Central Administrative Tribunal, Bangalore.

A copy of the Order passed by this Tribunal in the above sold application(s) is enclosed herewith for your information and buther necessary action.

The Order was prounounced on dated

SUR DEPUTY REGISTRAR 19/4/07/ JUDICIAL BRANCHES.

The Chief General Manager Telecom BSNL, Karnataka Region 2. Bangalore-560 001

(By Shri Vishnu Bhat, A.C.G.S.C.)

O.A. NO. 269/2004

R. Sumantharaya beinte viteind S/O. Late R.V. Murthy R/at No.40, IV Main Road Bangalore-560 004

(By Advocate Shri A.R. Holla)

- July 1995 as EVolicery: 111 egal. and unconstitution By its Secretary Ministry of Personnel Public Grievances & Pensions Deptt. of Pensions and Lok Nayak Bhavan Khan Market, New Delhi-110 003
- The PostMaster General 2. Bangalore-560 001 es Vin CPC) in its second interim Repor

MUKESH KUMAR GUPTA. tremulome !

reckoning

question of law and facts these cases, they are being disposed of by the sent common order. a divity be enhanced to be accepted by the Government

None appeared for the respondents despite service Nos. 171/04, 172/04, 209 & 259 to 260/04, 217/04, 241/04 & 269/04. As far as O.A. Nos. 218/04 & 264/04 are concerned, notices were issued but neither acknowledgements

were received back nor any one appeared for the real in O.A. No.776/2003, 2 sets of identical reply have filed without showing any justification as to what time the identical reply was filed. Such practice cannot allowed.

- service between 1st July, 1993 and 31st March, 1995.

 principal grievance of the applicants is to declare the of effect notified as 1st April, 1995 in O.M. dated July, 1995 as arbitrary, illegal and unconstitutional also to quash the O.M dated 18th February, 2003 issued the Department of Pension and Pensioners' Welfare, New Department of treatment of D.A. as emoluments gratuity with effect from 1.1.1996.
- The Vth Central Pay Commission (for short references as Vth CPC) in its second Interim Report Geommended in Dearness Allowance linked to average All India Consumers

The PostWaster General

Price Index (AICPI) 1201.66 as on 1.7.1993 be treated Dearness Pay for reckoning emoluments for the purpose ta-cum-Retirement Gratuity under Civi the Central rvite (Pension) Rules, 1972 and further that the ceiling recommendation on stratuity be enhanced to 2.50 lakhs. The to be accepted by the Government of India and it # olvies of ige decided that Dearness Allowance linked to the AICPI 1201.86 Department # India, Olificated in the Government of Pension and Pensioners Welfare OM No.7/1/95 P&PW (F) date nemended wond 14.7.11995, would be treated as dearness pay, for the purpos



cellet brayed for canno; of (Pension) Rules, 1972 of (Pension) Rules, 1972 "in the case of the Central government employees who retired or died on or We heard learned counsel for tendin and payment the pleadings.

The validity of the O.M dated 14th July, 1990 which was made operative with effect from 1st April, 1995 came up for consideration before a Full Berch of this Tribunal at Mumbai in the case of a Baburao Shankar Dhuri vs. Union of India and Others, 2001 (3) ATJ 438 and Ors. wherein the said cut off date, i.e. 1st April, 1995 was held to be discriminatory. The operative portion of the order and judgement read as follows: the said judgement. It was further contended that

" We do not find that there is any nexus or rational consideration in fixing the cut off date of first April, 1995 vide OM No.7/1/95-P&PW(F) dated 14th July (sic.) 1995 vide . OM issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension (Department of Pension Pensioners' Welfare), New Delhi.

aforesaid claim was resis

It is contended by the applicants that since retired in between 1st July 1993 and 31st March, 1995 they are entitled to the benefit of claim of merger of DA in pay for the purpose of emoluments calculating death/retirement gratuity. In other words, the contention is that the applicants are entitled to extension of the benefit of the said order passed by the respondents On the other hand, Full Bench.

contested the present applications by contending that the relief prayed for cannot be granted as they run counter to the recommendations made by the Vth CPC. getvice (Peneton) Rutes, 1972 "in the cese of the Central

Government employees who retired or died on or after learned counsel for the parties at length and perused the pleadings.

Jest , Vist of the D.M. dated 1410 July, 1890 7. Shri A.R. Holla, Shri R.G. Gayathri, Shri V Doralswamy, Shri Jagdish Patil, Shri B. Venkatesan and Shri M.S. Anandaramu appearing for the applicants strenuously urged that since the judgement rendered by the Full Bench of this Tribunal in Baburao Shankar Dhur; and Others case was a judgement in rem, the applicants being similarly placed, are entitled to the benefit of the said judgement. It was further contended that this Bench in a batch of cases decided on 30th October, 2003 followed the said Full Bench judgement and therefore, ADMIN entitled to the extension of the benefit of the

Full Bench Judgement and order.

aforesaid claim was resisted by the is/The and to basically on two grounds:- firstly, that the present applications are barred by limitation and a such not maintainable and secondly, that the issues raised in the present cases are under consideration before Hon'ble Supreme Court. Against the judgement and order passed by the Chandigarh Bench of this Tribunet in an identical case, which was upheld by the High Court of Full Bench. the other hand, respondents have

operation has been stayed by the Hon'ble Supreme Court of order dated 6th January, 2003. Therefore, the vide order applications should be disposed of without present applications contended the respondents.

As far as the question of limitation is concerned, we may note that a Division Bench of this concerned, we may note that a Division Bench of this ribunal vide order dated 30th October, 2003 passed in patch of cases has already rejected the said plea and therefore, we do not find any substance in the said therefore, we do not find any substance in the said contention. Accordingly, the plea of limitation is rejected.

note that it is undisputed fact that based on the order dated 6th January, 2003 passed in SLP (civ.) No.18367/02, the Hon'ble Supreme Court not only granted the Leave against the order and Judgement of Punjab and Haryana High Court but even stayed the operation of the said judgement. Based on the said order dated 6th January, 2003, Chandigarh Bench of this Tribunal, in R.A. No.134/02 in O.A. 636/PB/2002, passed order dated 6th June, 2003 and recalled and modified its earlier dated 10th July 2002. It was further ordered that the applicant would be granted the benefit as praced for only after the outcome of the decision of the soreme Court, if it was favourable to him.

treated as a distinct and separate

at it.

injab and Haryana, the Leave was granted and its

11. S/Shri A.N.V. Gowda, M.V. Rao, V.N. Holla.

Amaresh, Vishnu Bhat, K.N. Chandrashekar, Sugumaran and Smt. Swetha Anand appearing for the respondents contended that in service jurisprudence the theory is to extend the benefit of judgement and order to those who do not approach the Court as long as the judgement/order

was based on the principles, the object being to avoid multiplicity of proceedings and save the burden of exchequer.

12. It was further contended that since the issue raised in the present cases had been the subject matter before various Benches of this Tribunal, and is not seized of by different High Courts as well as Hon'ble Supreme Court of India, this Tribunal should regulate the relief so prayed for based on the decision to be taken by the Hon'ble Supreme Court. Shri N. Amaresh ADMINISTERCHED counsel for the respondents drew our attention

recommendation were to be given effect only from 1st

recommendations is extracted hereunder:-

"1.43 The Commission submitted its first Report, which pertained to interim Relief to pensioners, on 21st October, 1994 it was recommended that all pensioners and family pensioners be sanctioned an interim Relief at a uniform rate of Rs. 50 per month. This was to be treated as a distinct and separate element to be set off

The Second Report of the Commission vas recommended. Government on 2nd May, submitted to finally : recommended the grant of Interim Relief equal to 10% of recommends subject to a minimum of Rs. 100/- per month. pay:

ic pay:

ic ther instalment of Interim Relief equal to 10% of pasic pension/family pension subject to a minimum of the part month was also recommended. It was minimum of the 50 per month was also recommended. It was suggested Rs. Dearness Allowance liked to the average AICPI that 66 as on July 1, 1993 be treated as dearness pay 1201 reckoning emoluments for the purpose of retirement for death gratuities, and the ceiling on gratuity be and death to Rs. 2.5 lakhs. These recommendations were enhanced ven effect to from 1st April. 1995." (emphasis supplied)

twas further contended that this being the fact and the law being so settled that the Government can decide as a matter of policy the date from which the benefit be regulated, the Tribunal was not justified in holding the gaid date of 1st April, 1995 as illegal and arbitrary.

Shri A.N.V. Gowda, learned counsel for the respondents contended that prima facie case was made out before the Hon'ble Supreme Court and Leave has since been granted as well as other procedural aspects. i.e. preparation of paper books etc. being dispensed with and therefore this Tribunal should avoid further litigation in the interest of applicants as well as to avoid multiplicity of proceedings, and also regulate the of the applicants in terms of the decision to be the Hon'ble Supreme Court. It was further

against which writ petitions have been preferred which new exchar been before different High Courts and the matter is seized of by them. It was further argued on treatings filed by

out that various Benches of this Tribunal have

The state of the state of

behalf of the respondents that the pleadings filed by

1

The second services and services are services and services are services and services and services are services and services and services and services are services and service the applicants do not even remotely show that any or the applicants have even made any representation to concerned authorities seeking extension of the said order and judgement passed by the Full Bench. order and judgement passed by the rule senting of the branch of the senting of the passed of the senting of the

Shri A.R. Holla, learned counsel fur eleangma) ___egg applicants agreed with the contention raised by the respondents that allowing the applications would result the law beings ad settled that the Covernment in multiplicity of proceedings but added that the of illegal chartest the englicants intense Tribunal should protect the applicants interests too. regulated, the Tribunal was not justified in helding the

seid date of 18th April 1995 as illegal and arbitrary. Without going into the merit and the contentions raised by the parties, though in the normal nhi Al.N.Vilo Gowdayo learned counsel for the circumstances we would have followed the judgement rendered by the Full Bench of the Tribunal in before the Honfble Supreme Court, and Leave has since aforementioned cases but in order to avoid multiplicity beene granted; asoweld as other procedure as of proceedings and further litigation as well as in preparation of paper books etc. being dispensed of applicants, and milherefore inthemeterglerell should interest circumstances as noted herein above, we are of litigation in the interest of applicants as well eldered view that the present applications can be seed of as the Hon'ble Supreme Court is seized of ssue in question as mentioned above and may lay the Honbble Supreme Court. downthe law applicable to all irrespective of the fact oute that wanious Senches of this ther one is party before it or not. We are also of add based the order in favour the considered opinion that in case we allow the claim need even enolited line thatdw. Neglige of the applicants, who are pensioners and are within the age group of 67 - 69 years, it would be difficult for

behalf of the respondents that the pleadings filed

the Hon'ble Supreme Court decide the matter in some other way.

Accordingly, the applications are disposed of the direction that the claim of the applicants for the direction of pension as well as death-cum direction would be regulated based upon the judgement to be rendered by the Hon'ble Supreme Court in Civil Appeals as well as connected petitions/appeals as cited above. There shall be no order as to costs.

(MUKESH KUMAR GUPTA)
MEMBER (J)

(S.K. WAJFA)
MEMBER (A)

np/mr.



तस्य प्रति । TRUE COPY

अनुमाग अधिकारी Section Officer

. केंग्रीत तत्तात्ति अधिकारण Central Administret 😕 ीibungi

बें (ब्रंट नावज्ञ हे ज्लू Bangaiora Banch, Bungaiora,

Annexure-III

Decision of Hon'ble Supreme Court in the case of Sh. Pritam Singh Vs UOI

The decision of the Controlling Authority, Yamuna Nagar for payment of gratuity to Sh. Pritam Singh under the Payment of payment of the payment of the failure of the respondent Gratuity to convince the said Authority about non-applicability of Railway to Railway to Railway to Singh. It could be observed from Singh. It could be observed from the Payment of Gratuity Act, 1972 to Shri the provision. It could be observed from the decision of the pritam Sing Suthority Yamuna Nagar that though the Railway had maintained that dearness allowance did not form part of the maintain and a support thereof does not appear and a single the rule position in support thereof does not appear to have been brought out clearly with the result the Controlling Authority came to the conclusion that dearness allowance formed part of "wages" for calculation of gratuity under the Payment of Gratuity Act, 1972 and that Sh. Pritam Singh should be paid gratuity accordingly. The interpretation given by the Controlling Authority to the definition of the term 'Wages' in the Payment of Gratuity Act, 1972, is, no doubt, correct, but the issue as to whether this Act itself was applicable to Sh. Pritam Singh or not was not explained in sufficient detail during hearing of the case by the Controlling Authority. Had the Railway submitted its position in a convincing manner to establish that since Pritam Singh was a Railway servant at the time of his retirement and that he was governed by the Railway Pension Rules and not by the provisions under the Payment of Gratuity Act, 1972, the Controlling Authority would perhaps not have given a ruling in favour of Sh. Pritam Singh.

2. The provisions of the Payment of Gratuity Act, 1972 are applicable only to those employees who do not hold any post under the Government. As such, these provisions do not apply to a Railway servant, who holds a post on the Railways. definition of the term 'employee' as appearing in para 2 (e) of the Act reads as under:-

"employee" means any person (other than an apprentice) employed on wages, in any establishment, factory, mine, oilfield, plantation, port, railway company or shop to do any skilled, semi-skilled, or unskilled, manual, supervisory, technical or clerical work, whether the terms of such

employment are express or implied, and whether or not such person is employed in a managerial or administrative person is employed in a management of a State Government of a Stat capacity, but does not include any such post under the Central Government or a State Government post under the Central Government or a State Government or post under the Central Government and is governed by any other Act or by any rules providing The decision of the C. viiutare to tnemyad not muna Nagar for

On the Railways, casual labourers, including the temporary status On the Railways, casual labourers, including status assigned casual labourers, who do not hold any posts assigned by the provisions of the Payment of Gratuity Act 100 are governed by the provisions of the Payment of Gratuity Act, 1972 When they cease to be in service while holding the status of When they cease to be in service will act status of the stipulations laid down therein.

- 3. The decision of the Controlling Authority, Yamunanagar in the case of Shri Pritam Singh, as upheld by the CAT/Chandigarh and the Supreme Court, had to be implemented as a judgement 'Personem'. There was no option except to implement the judgement because the Railway was not able to substantiate nonapplicability of the provisions under the Payment of Gratuity Act 1972 to Sh. Pritam Singh, who was holding a post under the doubt, correct, but the issue as to whether exeminal itself is applicable to Sh. Pritam Singh or not was not explained
- 4. Railway employees who were holding posts under the Govt and retired during 1.1.1986 to 15.9.1993 were settled under the Railway Pension Rules: 9 The said rules provided for reckoning the basic pay alone for calculation of gratuity. In respect of those who retired/died during 16.9.1993 - 31.3.1995, 20% of the basic pay was reckoned as emoluments in addition to the basic pay for calculating gratuity and in respect of those who retired during 1.4.1995 - 31.12.1995, dearness allowance linked to AICPI-1201.66 was to be treated as emoluments along with the basic pay yns for calculating gratuity. yolgme esont of ylno eldesilgas under the Government. As such, these provisions do not app a Railway servant, with holds a post on the Railways.

Act reads as under:-"employee" means any person (other than an appre employed on wages, in any establishment, factory, oilfield, plantation, port, railway company or shop to d skilled, semi-skilled, or unskilled, manual, supen technical or clerical work, whether the terms of

definition of the term 'employee' as appearing in para 2 (e) c